

सिरी राम बत्रा और अन्य

बनाम

वित्तीय आयुक्त, दिल्ली और अन्य

सितंबर 17, 2004

[न्यायाधिपति शिवराज वी. पाटिल और न्यायाधिपति बी. एन. श्रीकृष्णा]

पूर्वी पंजाब जोत (विखंडन एवं विखंडन की रोकथाम) अधिनियम, 1948-धारा 36-बेशी फिरनी पुराने भूमिदारों के लिए चकबंदी लाभ की संशोधित योजना का प्रावधान - भूमिदारों को संशोधन के समय भूमि में रुचि नहीं है, वे योजना के लाभ के हकदार नहीं हैं।

कानून की व्याख्या-किसी कानून को उस वस्तु या उद्देश्य के संदर्भ में सार्थक और उद्देश्यपूर्ण ढंग से पढ़ा और समझा जाना चाहिए जिसे वह प्राप्त करना चाहता है।

वर्ष 1987 में चकबंदी की मूल योजना लागू होने पर प्रतिवादी संख्या 4 की भूमि को फिरनी (लालडोरा) में शामिल किया गया था। योजना के अनुसार उन्हें क्षेत्र संख्या 1244 के बदले में कृषि भूमि का तीन गुना क्षेत्र आवंटित किया गया था। इस प्रकार आवंटित क्षेत्र फ़ील्ड संख्या 28/12, 28/19 और 28/22 में शामिल था। वर्ष 1988 में प्रतिवादी संख्या 4 ने किला संख्या 28/22 में अपनी 4 बीघे और 9 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 3 को बेच दी। चकबंदी अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 25.3.1992 द्वारा, प्रतिवादी संख्या 3 को किला संख्या 28/22 के बदले में किला संख्या 102/19 और 102/20 बनाते हुए समान क्षेत्र आवंटित किया, जिसे चकबंदी की योजना में संशोधन के परिणामस्वरूप लालडोरा में शामिल किया गया था।

प्रतिवादी संख्या 3 ने वित्तीय आयुक्त, दिल्ली के समक्ष पूर्वी पंजाब होल्डिंग (एकीकरण और विखंडन की रोकथाम) अधिनियम, 1948 की धारा 42 के तहत एक

पुनरीक्षण याचिका दायर की, इस आधार पर कि चकबंदी अधिकारी ने उसे बेशी फिरनी का लाभ नहीं देकर गलती की थी। संशोधित योजना के अनुसार फिरनी में शामिल उसकी भूमि के मूल्य का तीन गुना मूल्य उसे आवंटित न करके। चकबंदी अधिकारी ने कहा कि विस्तारित फिरनी के भीतर किला संख्या 28/22 को शामिल करने के परिणामस्वरूप बेशी फिरनी अपीलकर्ताओं को इस आधार पर दी गई थी कि किला संख्या 28/22 वास्तव में पूर्व-चकबंदी खसरा संख्या 324 का गठन करता था, जो कि उनकी भूमिदारी, कि बेशी फिरनी का लाभ पिछले/मूल भूमिदारों को दिया जाना था और प्रतिवादी संख्या 3 इस तरह के लाभ का हकदार नहीं था क्योंकि उसने प्रश्न में भूमि खरीदी थी, जो कि मूल योजना के गठन के बहुत बाद उसके नाम पर बदल दी गई थी। अपीलकर्ताओं-पुराने भूमिदारों को पुनरीक्षण याचिका में पक्षकार बनाया गया था। वित्तीय आयुक्त ने अपीलकर्ताओं द्वारा दायर प्रतिवादी संख्या 3 रिट याचिका के दावे को खारिज कर दिया। लेटर्स पेटेंट अपील भी खारिज कर दी गई।

इससे पहले अदालत में अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 36 के तहत जारी संशोधित योजना के आधार पर वे पुराने भूमिदार होने के नाते किला नंबर 28/22 में भूमि को शामिल करने के परिणामस्वरूप लाभ के हकदार थे, प्रतिवादी नंबर 3 पुराना नहीं था। भूमिदार और इस योजना के तहत अपीलकर्ता लाभ के हकदार थे, यदि "पुराने भूमिदार" (साबिक भूमिदार) शब्दों के उपयोग का कोई अर्थ दिया जाना है।

प्रतिवादी नंबर 3 ने तर्क दिया कि नीचे दिए गए न्यायालयों ने इस योजना की सही व्याख्या की है कि प्रतिवादी नंबर 3 को योजना के तहत लाभ उपलब्ध था और अन्यथा योजना की व्याख्या करने से बेतुकापन हो जाएगा और/या कानून की व्याख्या के नियम ऐसी अनुमति नहीं देते हैं एक व्याख्या दी जानी है।

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए माना गया:

1. वित्तीय आयुक्त द्वारा अनुबंध पी-1 पर दी गई व्याख्या, जैसा कि एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पुष्टि की गई है, एक सही व्याख्या है। अपीलकर्ताओं ने खसरा नंबर 324 वाली भूमि पर अपना अधिकार खो दिया है और इसके बदले में भूमि नंबर 679 प्राप्त कर लिया है, उनके पास खसरा नंबर 324 वाली भूमि पर कोई अधिकार या हित नहीं है, ताकि संशोधित योजना के तहत किसी भी लाभ का दावा किया जा सके। जब वे प्रासंगिक तिथि पर भूमिदार नहीं रहे और अनुबंध पी 1 के तहत उन व्यक्तियों को लाभ दिया जाना है, जिन्होंने अपनी भूमि खो दी है, उन्हें मुआवजा देने के लिए। अपीलकर्ताओं ने विस्तारित लालडोरा के कारण नई योजना के तहत कोई जमीन नहीं खोई। किला संख्या 28/22 में भूमि के संबंध में मूल भूमिदार प्रतिवादी संख्या 4 होगा। (478-सी, डी)

2. यह बेटुका है कि जिस व्यक्ति का अब प्लॉट नंबर 324 में कोई अधिकार नहीं है, उसे फिर भी संशोधन का लाभ मिलना चाहिए। ऐसी अधीनता स्वीकार करने से अन्याय और अनौचित्य को बढ़ावा मिलेगा। व्याख्या का कोई भी नियम ऐसी व्याख्या की अनुमति नहीं दे सकता। [477 एफ, जी]

3. योजना अनुबंध पी-1 को दी गई पृष्ठभूमि में संपूर्ण रूप से पढ़ा और समझा जाना चाहिए। अन्यथा, अनुलग्नक पी-1 में निहित प्रावधान कि "हालांकि, जिन भूमिदारों को 21 (1) के तहत पूर्व चकबंदी क्षेत्र आवंटित किया गया था और उसे खरीददारों को बेच दिया गया है, वे उपरोक्त लाभ के हकदार होंगे", अर्थहीन या अनावश्यक होगा। अनुबंध पी-1 को कानून के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता। यहां तक कि किसी कानून को भी उस वस्तु या उद्देश्य के संदर्भ में सार्थक और उद्देश्यपूर्ण ढंग से पढ़ा और समझा जाना चाहिए जिसे वह प्राप्त करना चाहता है। [477-एच; 478-ए, बी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 4551/2000

1999 के एलपी.ए संख्या 468 में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 26.10.99 से।

अपीलार्थियों के लिए एन. एन. गोस्वामी, तारा चंद्र शर्मा, राजेंद्र दत्त, सुश्री नीलम शर्मा और तरुण शर्मा।

उत्तरदाताओं की ओर से अल्ताफ अहमद, डी. एन. रे और श्रीमती सुमिता रे।  
न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था-

न्यायाधिपति शिवराज वी. पाटिल :

निर्धारण के लिए एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या अपीलकर्ता 12.8.1991 पर पुष्टि की गई समेकन की संशोधित योजना के परिणामस्वरूप विस्तारित फिरनी के भीतर किला संख्या 28/22 को शामिल करने के परिणामस्वरूप बेशी फिरनी क्षेत्र के आवंटन के लाभ के हकदार हैं।

इस अपील में प्रतिवादी संख्या 4, दिनेश कुमार, चकबंदी की कार्यवाही शुरू होने के समय अलीपुर में क्षेत्र संख्या 1244 में भूमि का हकदार था। वर्ष 1987 में चकबंदी की मूल योजना लागू होने पर उक्त भूमि को फिमी (लालडोरा) में शामिल किया गया था। योजना के अनुसार उन्हें खेत संख्या 1244 के बदले में कृषि भूमि का तीन गुना क्षेत्रफल आवंटित किया गया था। इस प्रकार आवंटित क्षेत्र फ़ील्ड संख्या 28/12, 28/19 और 28/22 में शामिल था। तदनुसार, वर्ष 1987 में पुनर्विभाजन की कार्यवाही के दौरान उन्हें उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया गया। इसके बाद, वर्ष 1988 में प्रतिवादी संख्या 4 ने किला संख्या 28/22 में 4 बीघे और 9 बिस्वासिन की अपनी जमीन वर्ष 1988 में गौतम जैन को बेच दी। , यहां प्रतिवादी क्रमांक 3। यह किला संख्या 28/22 पहले खसरा नंबर 324 था, यानी पूर्व चकबंदी खेत नंबर।चूंकि प्रतिवादी नंबर 4 ने पहले ही लालडोरा में फ़ील्ड नंबर 1244 में अपनी भूमि को शामिल करने का लाभ ले लिया था, इसलिए चकबंदी अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 25.3.1992 द्वारा

प्रतिवादी नंबर 3 को किला संख्या 102/19 और 102/20 बनाते हुए समान क्षेत्र आवंटित किया। किला संख्या 28/22 के बदले में, जिसे चकबंदी योजना के संशोधन के परिणामस्वरूप लालडोरा में शामिल किया गया था। प्रतिवादी संख्या 3 ने पूर्वी पंजाब होल्डिंग (एकीकरण और विखंडन की रोकथाम) अधिनियम, 1948 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 42 के तहत वित्तीय आयुक्त, दिल्ली के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिसमें शिकायत की गई कि चकबंदी अधिकारी ने एक अपराध किया है। संशोधित योजना के अनुसार फिरनी में शामिल उसकी भूमि के मूल्य का तीन गुना मूल्य आवंटित न करके उसे बेशी फिरनी का लाभ न देने में त्रुटि हुई। चकबंदी अधिकारी ने पुनरीक्षण याचिका पर दी गई टिप्पणियों में कहा कि विस्तारित फिरनी के भीतर किला संख्या 28/22 को शामिल करने के परिणामस्वरूप बेशी फिरनी अपीलकर्ताओं को इस आधार पर दी गई है कि किला संख्या 28/22 वास्तव में पूर्व चकबंदी खसरा नंबर 324 बना, जो उनकी भूमिदारी में था। आगे यह बताया गया कि बेशी फिरनी का लाभ पिछले/मूल भूमिदारों को दिया जाना था और प्रतिवादी संख्या 3 इस तरह के लाभ का हकदार नहीं था क्योंकि उसने प्रश्न में जमीन खरीदी थी, जो उसके "बहुत बाद के नाम" में बदल दी गई थी। मूल योजना का गठन। टिप्पणियों के मद्देनजर अपीलकर्ताओं को पुनरीक्षण याचिका में पार्टियों के रूप में शामिल किया गया था। विद्वान वित्तीय आयुक्त ने अपने सामने रखी गई सामग्री के आलोक में पार्टियों के संबंधित तर्कों पर विस्तार से विचार करने के बाद प्रतिवादी नंबर 3 के दावे की अनुमति दी। आदेश दिनांक 23.10.1992 द्वारा। वित्तीय आयुक्त के उक्त आदेश से व्यथित अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष 1993 की सिविल रिट याचिका संख्या 68 दायर की। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने एक विस्तृत और सुविचारित आदेश द्वारा रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं पाई। परिणामस्वरूप रिट याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद, अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष 1999 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 468 दायर की। आक्षेपित निर्णय से,

उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने वित्तीय आयुक्त के आदेश की पुष्टि करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से सहमत होकर अपील को खारिज कर दिया। इसलिए यह अपील की गई है।

अपीलकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने अधिनियम की धारा 36 (अनुलग्नक पी-1 - अनुवादित संस्करण) के तहत जारी संशोधित योजना के आधार पर आग्रह किया कि अपीलकर्ता पुराने भूमिदार होने के कारण इसमें शामिल होने के परिणामस्वरूप लाभ के हकदार थे। भूमि किला नंबर 28/22 (मूल खसरा संख्या 324), जिसके अपीलकर्ता भूमिदार थे। विशेष रूप से उन्होंने हमारा ध्यान अनुलग्नक पी-1 के उस भाग की ओर आकर्षित किया, "भूखण्ड आवंटित करते समय आवंटन का अधिकार पुराने भूमिदारों का ही होगा, यदि उनका नाम सूची में अंकित हो।" उनके अनुसार प्रतिवादी क्रमांक 3 पुराना भूमिदार नहीं है। विद्वान वकील ने आग्रह किया कि योजना के तहत अपीलकर्ता लाभ के हकदार थे, यदि अनुबंध पी -1 में "पुराने भूमिदार" (साबिक भूमिदार) शब्द के उपयोग का कोई अर्थ दिया जाना है।

इसके विपरीत, प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि वित्तीय आयुक्त, विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अनुलग्नक पी-1 की सही व्याख्या करते हुए कहा है कि प्रतिवादी संख्या 3 को योजना के तहत लाभ उपलब्ध था। उन्होंने विशेष रूप से योजना के उस हिस्से की ओर ध्यान दिलाया, "हालांकि, जिन भूमिदारों को 21 (1) के तहत पूर्व चकबंदी क्षेत्र आवंटित किया गया था और उसे खरीददारों को बेच दिया गया है, वे उपरोक्त लाभ के हकदार होंगे"। अनुलग्नक पी-1 में इस प्रावधान के मद्देनजर, आक्षेपित निर्णय में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है।

हमने पक्षों के विद्वान वकील द्वारा दी गई दलीलों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है।

अपीलकर्ता ग्राम अलीपुर में खसरा संख्या 324 वाली भूमि के मूल भूमिदार थे। यह जमीन लालडोरा में शामिल थी। उनके आवेदन के अनुसार अपीलकर्ताओं को खसरा संख्या 324 वाली भूमि के बदले प्लॉट संख्या 679 आवंटित किया गया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। इस प्रकार, जैसा कि ऊपर कहा गया है, अपीलकर्ताओं का भूखंड संख्या 679 को स्वीकार करने के बाद भूमि संख्या 324 पर कोई अधिकार या हित नहीं रह गया है। इसके बाद खसरा संख्या 324 वाली भूमि प्रतिवादी संख्या 4 को उसके प्लॉट संख्या 1244 के बदले आवंटित कर दी गई, जो लालडोरा क्षेत्र में शामिल था।

संबंधित की सराहना करने के लिए भौतिक घटनाओं पर ध्यान देना बेहतर है

विवाद वर्ष 1987 में अधिनियम के तहत ग्राम अलीपुर में चकबंदी की कार्यवाही शुरू की गई थी। अधिनियम की धारा 19 के तहत तैयार की गई चकबंदी योजना की उक्त गांव के संबंध में बंदोबस्त अधिकारी द्वारा 24.7.1987 को अधिनियम की धारा 20 के तहत पुष्टि की गई थी। प्रतिवादी क्रमांक 4 उक्त गांव के खेत क्रमांक 1244 की भूमि का अधिकार धारक था। वर्ष 1987 में चकबंदी की मूल योजना लागू होने पर इस भूमि को फिरनी (लालडोरा) में शामिल किया गया था। उन्हें इस भूमि को विस्तारित लालडोरा में शामिल करने का लाभ मिला और उन्हें पूर्व-चकबंदी क्षेत्र की कृषि भूमि का तीन गुना क्षेत्र आवंटित किया गया, जिसमें तीन फ़ील्ड नंबर शामिल थे, जिन्हें पुनर्विभाजन के दौरान नए किला नंबर दिए गए, अर्थात् 28/12, 28/ 19 और 28/22 (पूर्व चकबंदी क्षेत्र संख्या 324) प्रत्येक की माप 4 बीघा और 9 बिस्वा है। इसके बाद, उन्होंने वर्ष 1988 में अपनी भूमि किला संख्या 28/22 प्रतिवादी संख्या 3 को बेच दी। इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या 4 ने अपनी भूमि क्षेत्र संख्या 1244 को शामिल करने के बदले में लाभ उठाया था। योजना में 24.7 को संशोधन किया गया था। 1991, यानी प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा भूमि किला संख्या 28/22 खरीदने के काफी समय बाद।

चकबंदी की संशोधित योजना के तहत संख्या 324 सहित विभिन्न क्षेत्र संख्या में शामिल 56 बीघे और 6 बिस्वा भूमि को शामिल करके लालडोरा का विस्तार किया गया था।

ऊपर उल्लिखित घटनाओं से, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता उस तारीख से क्षेत्र संख्या 324 के भूमिदार नहीं रहे, जिस दिन उन्हें भूमि क्षेत्र संख्या 679 मिली थी, जिसे उन्होंने भूमि संख्या 324 के बदले में स्वीकार किया था। इसके बाद, प्रतिवादी क्रमांक 4 किला नंबर 28/22 (पुराना खसरा नंबर 324) का मालिक बन गया क्योंकि यह उसे उसकी भूमि नंबर 1244 में शामिल करने के बदले आवंटित किया गया था, इसके अलावा, प्रतिवादी नंबर 3 ने उक्त जमीन बहुत बाद में खरीदी थी। चकबंदी की संशोधित योजना के अनुमोदन की तिथि के अनुसार प्रतिवादी संख्या 3 इस भूमि का मालिक था, जिसने इसे प्रतिवादी संख्या 4 से पंजीकृत बिक्री विलेख के तहत खरीदा था।

वित्तीय आयुक्त ने अपने आदेश में, संशोधित योजना के हिंदी संस्करण (अनुलग्नक पी-1) को देखते हुए, इस प्रकार कहा: -

"यह विवाद समेकन की संशोधित योजना के हिंदी संस्करण को पढ़ने से शांत हो गया है, जो स्थिति को बढ़ाता है। इसमें यह निर्धारित किया गया है कि बेशी फिरनी मूल योजना के अनुसार मूल अधिकार धारक के पास जाएगी। हालाँकि, ऐसे मामलों में, जिन अधिकार धारकों ने अधिनियम की धारा 21 (1) के तहत पुनर्विभाजन के बाद भूमि हस्तांतरित की है, बेशी फिरनी का लाभ क्रेता को मिलेगा। यहां, इस मामले में, माना जाता है कि उत्तरदाताओं संख्या 4, 5 और 6 को आवंटित किया गया था खसरा संख्या 324 के बदले में पुनर्विभाजन के दौरान भूखंड संख्या 679। उन्होंने इस आवंटन के खिलाफ कोई



आपत्ति नहीं उठाई। नतीजतन, भूखंड संख्या 679 का आवंटन अंतिम हो गया। इन उत्तरदाताओं का यह भी मामला नहीं है कि खसरा संख्या 324 को इसमें शामिल किया गया था समेकन की मूल योजना में विस्तारित फ़िमी। ऐसा होने पर, बेशी फिरनी के लाभ का उनका अधिकार उस चरण में ही माफ कर दिया गया था। किला नंबर 28/22 निश्चित रूप से चकबंदी पूर्व खसरा नंबर 324 का नया नंबर है। किला नंबर 28/22 का आवंटन श्री दिनेश कुमार को किला नंबर 28/12 और 28/19 के साथ धारा 21 (1) के तहत पुनर्विभाजन के दौरान किया गया था। उनके पूर्व चकबंदी खसरा नंबर 1244 के बदले में अधिनियम, जो गांव की मूल चकबंदी योजना के अनुसरण में विस्तारित फिरनी में उपभोग किया गया था और दिनेश कुमार को फिलहाल बेशी फिरनी का लाभ दिया गया था। बाद में, याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 21(1) के तहत दिनेश कुमार को आवंटित भूमि खरीद ली। अब, याचिकाकर्ता द्वारा खरीदी गई भूमि में से, किला नंबर 28/22 को चकबंदी की संशोधित योजना के अनुसार विस्तारित फिरनी में शामिल किया गया है, जाहिर तौर पर, अधिनियम की धारा 21 (1) के तहत आवंटन के बाद, दिनेश कुमार ने भूमि को हस्तांतरित कर दिया। चकबंदी की संशोधित योजना में, याचिकाकर्ता किला नंबर 28/22 का भूमिदार था, उसका मामला पूरी तरह से संशोधित योजना के प्रावधानों के तहत कवर किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से परिकल्पना की गई है कि अधिकार धारक के मामले में जिसने धारा 21 (1) के तहत पुनर्विभाजन के बाद भूमि हस्तांतरित की है। बेशी फिरनी का लाभ क्रेता को मिलेगा। निर्विवाद रूप से, याचिकाकर्ता प्रासंगिक समय पर किला नंबर 28/22 का

वास्तविक खरीदार था और इस तरह वह लाभ का पूरी तरह से हकदार है, जैसा कि उसके द्वारा दावा किया गया है।"

उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने आदेश में चकबंदी अधिकारी द्वारा दिनांक 25.3.1992 को दिए गए आदेश के ऑपरेटिव भाग को पुनः प्रस्तुत किया है, जिसमें लिखा है: -

"समेकन की अदालत में

अधिकारी: दिल्ली

वाद संख्या 3097 से 3105/सी.ओ ग्राम अलीपुर

आदेश की तिथि: 25.3.92.

वर्ष 1986 में ग्राम अलीपुर में चकबंदी की कार्यवाही के दौरान, कुछ भूमि धारक जो अपनी मांग के अनुसार आवासीय भूखंडों के अधिकार से वंचित थे, उन्होंने एस.ओ. (सी) की अदालत का रुख किया और उनमें से कुछ माननीय के पास गए। 'बल वित्तीय आयुक्त. आवासीय भूखंडों के आवंटन के लिए उनकी दलीलों को एस.ओ.(सी) और माननीय एफ.सी. द्वारा बरकरार रखा गया था। क्रमशः और विस्तारित आबादी में पीड़ित व्यक्तियों को आवासीय भूखंडों के आवंटन के लिए मामले वापस भेज दिए गए। उपरोक्त श्रेणी के भूमि धारकों को आवासीय भूखंडों के आवंटन की मांग को समायोजित करने की दृष्टि से अधिनियम की धारा 36 के तहत योजना में संशोधन किया गया था, जिन्हें पहले आवासीय भूखंडों और फिरनी से वंचित कर दिया गया था, जो 56 बिघा 6 बीस्वा के क्षेत्र के लिए विस्तारित थे। उत्तरी भाग. जिन लोगों को आवासीय भूखंड आवंटित किए जाने थे, उनमें से अधिकांश की मांग उत्तर या उत्तर-पश्चिम की ओर थी,

हालांकि, जय सिंह पुत्र भरत सिंह और छह अन्य ने दक्षिण-पूर्व दिशा में आबादी का विस्तार करने के लिए दिनांक 10.9.91 को एक आवेदन दायर किया था। इस आधार पर कि गांव में उनके घर उस तरफ स्थित हैं, इस प्रकार वे अपने घरों के पास भूखंड मांग रहे हैं। दक्षिण-पश्चिम दिशा में फिरनी का विस्तार करना संभव नहीं पाया गया क्योंकि जीटी से सटी हुई बड़ी संख्या में निर्मित संरचनाएं हैं। सड़क और पूर्व-विस्तारित फिरनी, यानी फार्म रोड। पूर्व दिशा में कोई जमीन नहीं है क्योंकि पूर्व विस्तारित फिरनी जी.टी.रोड को छूती है।"

विद्वान एकल न्यायाधीश ने, वित्तीय आयुक्त द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए और अनुबंध पी-1 के अनुसार संशोधित योजना को देखते हुए, रिट याचिका को सही ढंग से खारिज कर दिया।

उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने, जैसा कि आक्षेपित निर्णय से स्पष्ट है, वित्तीय आयुक्त के साथ-साथ विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश को देखा, दोनों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में कोई त्रुटि नहीं पाई। आक्षेपित निर्णय में यह देखा गया है कि

"प्लॉट नंबर 324 में अपीलकर्ताओं के अधिकार उसी समय समाप्त हो गए थे जब उन्हें विस्तारित लाल डोरा में प्लॉट नंबर 679 आवंटित और स्वीकार किया गया था। केवल इसलिए कि चकबंदी योजना में बाद में संशोधन हुआ था, इसका मतलब यह नहीं है कि पुराने अधिकार पुनर्जीवित हो जाएंगे। एक बार अपीलकर्ताओं ने प्लॉट नंबर 679 स्वीकार कर लिया तो उनके पास प्लॉट नंबर 324 में कोई और अधिकार नहीं था। यदि प्लॉट नंबर 324 अब संशोधित योजना में शामिल हो जाता है तो इसका लाभ क्रेता को जाना चाहिए।

इस बात पर जोर देकर आग्रह किया गया है कि उपरोक्त को मानने से बेतुकापन पैदा होगा और/या क़ानून की व्याख्या के नियम ऐसी व्याख्या की अनुमति नहीं देते हैं। हमारे विचार में यह कहना कि जिस व्यक्ति के पास अब प्लॉट नंबर 324 में कोई अधिकार नहीं है, उसे अभी भी संशोधन का लाभ मिलना चाहिए, एक बेतुका तर्क है। ऐसी अधीनता स्वीकार करने से अन्याय और अनौचित्य को बढ़ावा मिलेगा। व्याख्या का कोई भी नियम ऐसी व्याख्या की अनुमति नहीं दे सकता। इसलिए, हमें आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता।"

ऊपर जो कहा गया है, उसके मद्देनजर, हमें अपीलकर्ताओं की ओर से दिए गए तर्कों को स्वीकार करना मुश्किल लगता है कि वे केवल इस आधार पर भूमि के हकदार थे कि वे मूल भूमिदार थे। योजना अनुबंध पी-1 को दी गई पृष्ठभूमि में संपूर्ण रूप से पढ़ा और समझा जाना चाहिए। यदि अपीलकर्ताओं के लिए विद्वान वकील के तर्क को अनुबंध पी -1 में निहित प्रावधान को स्वीकार किया जाए कि "हालांकि, जिन भूमिदारों को 2 I (1) के तहत पूर्व चकबंदी क्षेत्र आवंटित किया गया था और उसे बेच दिया गया है, खरीदार इसके हकदार होंगे उपरोक्त लाभ", निरर्थक या अनावश्यक होगा। अनुबंध पी-1 को क़ानून के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता। यहां तक कि किसी क़ानून को भी उस वस्तु या उद्देश्य के संदर्भ में सार्थक और उद्देश्यपूर्ण ढंग से पढ़ा और समझा जाना चाहिए जिसे वह प्राप्त करना चाहता है।

हमारे विचार में, वित्तीय आयुक्त द्वारा अनुबंध पी-1 पर दी गई व्याख्या, जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ-साथ उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पुष्टि की गई है, एक सही व्याख्या है। अपीलकर्ताओं ने खसरा संख्या 324 वाली भूमि पर अपना अधिकार खो दिया है और इसके बदले में भूमि संख्या 679 प्राप्त कर ली है,

खसरा संख्या 324 वाली भूमि पर उनका कोई अधिकार या हित नहीं है, जिससे वे इसके तहत किसी भी लाभ का दावा कर सकें। संशोधित योजना जब वे प्रासंगिक तिथि पर भूमिदार नहीं रहे तो भूमिदार के रूप में और अनुबंध पी-1 के तहत उन व्यक्तियों को लाभ दिया जाना है, जिन्होंने अपनी भूमि खो दी है, ताकि उन्हें मुआवजा दिया जा सके। अपीलकर्ताओं ने विस्तारित लालडोरा के कारण नई योजना के तहत कोई जमीन नहीं खोई। भूमि किला संख्या 28/22 के संबंध में मूल भूमिदार प्रतिवादी संख्या 4 होगा।

इस प्रकार, किसी भी कोण से देखने पर आक्षेपित निर्णय में कोई दोष नहीं पाया जा सकता। इसलिए, हमें अपील में कोई योग्यता नहीं दिखती। परिणामस्वरूप इसे खारिज कर दिया गया है, लेकिन लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया है।

वी एम

अपील खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।